(1975) 2 SCR 57

नारायण देबनाथ

बनाम

पश्चिम बंगाल राज्य

13 सितंबर, 1974

[पी. गगनमोहन रेड्डी और पी. के. गोस्वामी, जे. जे.]

आंतरिक सुरक्षा का रखरखाव अधिनियम, 1971, धारा 3-हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका में अदालत द्वारा जांच का दायरा-चलती ट्रेन में सशस्त्र डकैती- सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करता है।

याचिकाकर्ता को आंतरिक सुरक्षा का रखरखाव अधिनियम, 1971 की धारा 3 के तहत हिरासत में लिया गया था, एकमात्र इस आधार पर कि रात लगभग 10 बजे, उसने अपने सहयोगियों के साथ, बंदूकों और अन्य हथियारों से लैस होकर, एक चलती ट्रेन के तीसरे दर्जे के डिब्बे में डकैती की। निरोध आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका में जिला मजिस्ट्रेट ने अपने जवाबी हलफनामे में कहा कि वह अपनी व्यक्तिपरक संतुष्टि को केवल निरोध आदेश में उल्लिखित आधार पर आधारित करते हैं, हालांकि उनके सामने अन्य तत्व भी रखे गए थे। इसलिए न्यायालय ने हिरासत में

लिए गए व्यक्ति के अभिलेख और इतिहास पत्र की जांच की और याचिका खारिज करते हुए माना कि:

(1) जिस आधार पर निरोध का आदेश दिया गया था, वह हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के मन में एक वास्तविक संतुष्टि को जन्म देगा कि ऐसी घटनाओं के उसी तरीके से दोहराए जाने की संभावना थी और जिन लोगों पर इस तरह की एक भी घटना में भाग लेने का आरोप लगाया गया था, उन्हें हिरासत में लेना पड़ा ताकि सार्वजनिक जीवन में शांति का माहौल खतरे में न पड़े। अभिलेख और हिस्ट्री शीट की सावधानीपूर्वक जांच से पता चला कि बंदी द्वारा किए गए कार्य की गंभीर प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, जिला मजिस्ट्रेट वास्तव में संतुष्ट थे कि उक्त अधिनियम निरोध आदेश देने के लिए पर्याप्त था। [58 एफ-जी; 60 ए-बी]

(2) इसका प्रतिवाद तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि आधारों में बताए गए तथ्य न्यायालय की संतुष्टि होने तक साबित नहीं हो जाते, अधिनियम के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शिकायत किए गए कार्य को न्यायालय में संतोषजनक रूप से साबित नहीं किया जा सकता है या कि गवाह पहले से ही किए गए कार्य की व्यापकता से भयभीत होने के कारण आगे आने के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए समान प्रकृति के अपराधों के आगे होने को रोकने के लिए अधिनियम के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए, [58 जी-एच]

इसके अलावा, इस तरह के मामले में जांच का दायरा बहुत सीमित है। न्यायालय को आधारों को सही मानना होगा और आधारों में उल्लिखित आरोपों की सच्चाई या अन्यथा की जांच करना उसका कार्य नहीं है। [58 एच]

(3) यह भी तर्क नहीं दिया जा सकता है कि मामला केवल कानून और व्यवस्था को प्रभावित करता है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था को नहीं। जब एक सशस्त्र डकैती या डकैती का आरोप लगाया जाता है जो याचिकाकर्ता द्वारा बंदूकों से लैस और अपने सहयोगियों के साथ एक चलती ट्रेन में किया गया है, तो यह अब साधारण कानून और व्यवस्था का विषय नहीं रहता है क्योंकि बड़े पैमाने पर समुदाय के जीवन का शांतिपूर्ण माहौल भी प्रभावित होती है। यह न केवल विशेष रूप से तृतीय श्रेणी के डिब्बे में विभिन्न स्थानों और सामाजिक पृष्ठभूमि के यात्रियों को डराता है, बल्कि पूरी ट्रेन और यहां तक कि अन्य चलने वाली ट्रेनों के यात्रियों को भी दहशत में डालता है। इस प्रकार सार्वजनिक व्यवस्था और समुदाय का जीवन स्पष्ट रूप से बाधित है और यह सार्वजनिक अव्यवस्था के बराबर है जिसे अधिनियम के तहत कार्रवाई द्वारा रोका जाना था। [59 ए-डी]

सुबल चंद्र घोष बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, ए. आई. आर. 1972 एस. सी. पी. 2146; अरुण घोष बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1970) 3

एस. सी. आर. 288; राम मनोहर लोहिया का मामला (1966) 1 एस. सी. आर. 709) पालन किया।

निर्णय:

मूल क्षेत्राधिकार: रिट याचिका संख्या 305/1974।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका।

याचिकाकर्ता की ओर से जी. नारायण राव।

प्रतिवादी की ओर से सुमित्रा चक्रवर्ती, जीएस चटर्जी और एसके बसु।

न्यायालय का निर्णय गोस्वामी, जे द्वारा सुनाया गया। याचिकाकर्ता को आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम, 1971 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 3 के तहत हिरासत में लिया गया है (ताकि उसे सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के प्रतिकूल तरीके से कार्य करने से रोका जा सके)। आदेश जिला मजिस्ट्रेट, नादिया द्वारा 11-4-73 को पारित किया गया था। जिस आधार पर आदेश दिया गया था वह इस प्रकार है: -

"1. कि 16-2-73 को 10.08 बजे से 10.14 बजे के बीच आपने अपने अन्य सहयोगियों के साथ बंदूक और अन्य हथियारों से लैस होकर राणाघाट शांतिपुर सेक्शन के हबीबपुर आरएस और लकीनारायणपुर जंक्शन आरएस के बीच चलती ट्रेन एस 110 डाउन के तीसरे श्रेणी के डिब्बे में लूटपाट की और कलकत्ता के श्री आशुतोष पाल से 30,0,00/ रुपये की नकदी छीन

ली, उसको गोलियों से घायल कर दिया और सभी यात्रियों को मौत का डर सताने लगा।

आपके कृत्य से वहां भ्रम, घबराहट और सार्वजनिक व्यवस्था अशांत हो गई।

इस प्रकार आपने सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के प्रतिकूल व्यवहार किया है।"

आदेश उस बंदी को दिया गया जिसने अभ्यावेदन दिया था, जिस पर सरकार ने विचार किया और खारिज कर दिया। हमें विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा पारित विभिन्न आदेशों की समय-सारणी के बारे में जानकारी दी गई है और हमें इसमें कोई अवैधता नहीं मिली है। वास्तव में, याचिकाकर्ता के लिए न्याय मित्र के रूप में उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री नारायण राव ने उस संबंध में अवैधता का कोई आधार नहीं उठाया है।

हालाँकि, जिला मजिस्ट्रेट ने अपने हलफनामे (पैराग्राफ 6) में कहा है कि उनकी व्यक्तिपरक संतुष्टि केवल हिरासत आदेश में उल्लिखित आधार पर आधारित थी, हालांकि अन्य तत्व भी उनके सामने रखे गए थे, हमने हिरासत में लिए गए बंदी के मामले के इतिहास के अभिलेख की जांच की। रिकॉर्ड और हिस्ट्री शीट की सावधानीपूर्वक जांच के बाद, हम पाते हैं कि जिला मजिस्ट्रेट, बंदी द्वारा किए गए कृत्य की गंभीर प्रकृति को ध्यान में

रखते हुए, इस बात से संतुष्ट थे कि उक्त कृत्य नजरबंदी आदेश देने के लिए पर्याप्त था। हालाँकि, श्री नारायण राव का मानना है कि जब तक आधारों में बताए गए तथ्यों से यह न्यायालय संतुष्ट नहीं होता, तब तक अधिनियम के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। हम इस दलील को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। इसका कारण यह है कि जिस कृत्य की शिकायत की गई है, उसे शायद अदालत में संतोषजनक ढंग से साबित नहीं किया जा सकता है या गवाह पहले से ही किए गए कृत्य की भयावहता से भयभीत होने के कारण आगे आने को तैयार नहीं हैं, इसलिए समान प्रकृति के अपराधों को रोकने के लिए कभी-कभी अधिनियम के तहत कार्रवाई करनी पड़ती है। इसके अलावा, आधार में उल्लिखित आरोपों की सत्यता या अन्यथा की जांच करना न्यायालय का कार्य नहीं है। न्यायालय द्वारा इन आधारों को सत्य माना गया है और यह अच्छी तरह से स्थापित है कि इस प्रकृति के मामले में जांच का दायरा बहुत सीमित है।

विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि सबसे खराब स्थिति में यह कानून और व्यवस्था को प्रभावित करने वाला मामला है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाला नहीं है। हम इस दलील को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। जब याचिकाकर्ता द्वारा बंदूकों से लैस अपने साथियों के साथ चलती ट्रेन में इस तरह की सशस्त्र डकैती या डकैती करने का

आरोप लगाया जाता है, तो साधारण कानून और व्यवस्था का मामला नहीं रह जाता बल्कि बड़े पैमाने पर समुदाय के जीवन में शांतिपूर्ण माहौल पर इसका असर पड़ता है। यह न केवल विभिन्न स्थानों और सामाजिक पृष्ठभूमि के यात्रियों को विशेष रूप से जो तीसरी श्रेणी के डिब्बे में यात्रा करने वालों को दहशत में डालता है बल्कि पूरी ट्रेन के यात्री और यहां तक कि दूसरी चलती ट्रेनों के यात्रियों को भी दहशत में डालता हैं। इससे सार्वजनिक-व्यवस्था और समुदाय का जीवन स्पष्ट रूप से बाधित हो गया है। यह सार्वजनिक अव्यवस्था के समान है जिसे अधिनियम के तहत कार्रवाई द्वारा रोका जाना चाहिए। इसके अलावा, चलती ट्रेन में इस तरह की दुस्साहसिक डकैती की खबर से यात्रा करने वाले लोगों को ट्रेन से आवागमन का लाभ उठाने से भी रोक सकता है। ऐसे परिणाम और प्रभाव सार्वजनिक व्यवस्था को निश्चित रूप से प्रभावित करते हैं जो सार्वजनिक अव्यवस्था के विपरीत है। यदि किसी प्राधिकार की आवश्यकता है तो हमारे पास एक एआईआर 1972 एससी पी. 2146 (सुबल चन्द्र घोष बनाम पश्चिम बंगाल राज्य) है, जिसमें हममें से एक (जगनमोहन रेड्डी, जे.) ने इस प्रकार कहा,

" आधार संख्या 1 में दिए गए तथ्य स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि उसके (बंदी के) खिलाफ आरोपित अपराध, यात्रियों की उपस्थिति में

दुस्साहसिक तरीके से किया गया, जो बहुत ही भयभीत करने वाला और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने वाला रहा होगा।"

अरुण घोष बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1970-3 एस सी आर 288) में भी इस न्यायालय ने सार्वजनिक व्यवस्था के प्रश्न पर विचार करते हुए निम्न प्रकार से टिप्पणी की:-

"यह प्रश्न कि क्या किसी व्यक्ति ने केवल कानून और व्यवस्था का उल्लंघन किया है, या इस तरह से कार्य किया है जिससे सार्वजनिक व्यवस्था में विघ्न हो सकता है, समाज पर अधिनियम की पहुंच के डायरे और सीमा का प्रश्न है। परीक्षण यह है: क्या इससे समुदाय के जीवन की सम गति और धारा में विघ्न होता है जिससे कि सार्वजनिक व्यवस्था में विघ्न हो सकता है, या, क्या यह समाज की शांति को प्रभावित किए बिना केवल एक व्यक्ति को प्रभावित करता है।"

इस न्यायालय के एक और फैसले, राम मनोहर लोहिया के मामले (1966- 1 एससीआर 709) में हिदायतुल्ला, जे. ने तब बहुमत के लिए बोलते हुए सार्वजनिक व्यवस्था की पूरी अवधारणा को एक सुरम्य भाषा में निम्न रूप से रखा था:

"इस प्रकार यह प्रतीत होगा कि जिस प्रकार इस न्यायालय के निर्णयों में 'सार्वजनिक व्यवस्था' को "राज्य की सुरक्षा" को प्रभावित करने

वाले विकारों की तुलना में कम गंभीरता के विकारों के रूप में समझा गया था, "कानून और व्यवस्था" को "सार्वजनिक व्यवस्था" को प्रभावित करने वाले विकारों की तुलना में कम गंभीरता के रूप में समझा गया है। हमें तीन संकेंद्रित वृतों की कल्पना करनी होगी। कानून और व्यवस्था सबसे बड़े वृत्त का प्रतिनिधित्व करता है जिसके भीतर अगला वृत्त सार्वजनिक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है और सबसे छोटा वृत्त राज्य की सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। तब यह देखना आसान होगा कि- एक अधिनियम सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है लेकिन राज्य की सुरक्षा को नहीं।

हमारा स्पष्ट मानना है कि इस मामले में जिस आधार पर हिरासत का आदेश दिया गया है, वह हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के मन में उचित संतुष्टि पैदा करेगा कि ऐसी घटनाएं उसी तरीके से दोहराई जाने की संभावना है और वे जिन पर इस आकार की किसी भी एक घटना में शामिल होने का आरोप है, उन्हें हिरासत में लेना पड़ा ताकि सार्वजनिक जीवन में शांति का माहौल खतरे में न पड़े। इसलिए, हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि आक्षेपित आदेश में कोई दुर्बलता नहीं है। याचिका विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है। नियम का निर्वहन किया जाता है।

वी.पी.एस याचिका खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक अशोक कुमार मीना द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।